डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जनवरी, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 जनवरी, 2022

| वर्ष 65 | अंक 15 | भोपाल | 1 जनवरी, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

वनोपज विक्रय कार्य का होगा विकेन्द्रीकरण : मुख्यमंत्री श्री चौहान

पायलेट प्रोजेक्ट किया जाएगा प्रारंभ ● पारम्परिक कृषि उत्पादों के साथ करेंगे चंदन की खेती

बाँस,शहद, महुआ और अन्य उत्पादों से बढ़ाएंगे वनवासियों की आय

बायर-सेलर मीट के अधिकाधिक आयोजन हों

वन-धन केंद्रों की उत्पादित सामग्री की होगी बेहतर विपणन व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने की वनोपज उत्पादों की ब्रांडिंग

विंध्या हर्बल उत्पादों को करें प्रोत्साहित

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वनोपज के विक्रय के वर्तमान प्रचलित कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वनवासियों और वन समितियों द्वारा प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु वनोपजों के प्र-संस्करण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। वन-धन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उनकी उत्पादित सामग्रियों की पुख्ता विपणन व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूँ, धान, चने का उत्पादन कार्य पारम्परिक रूप से बड़े पैमाने पर होता है। इन उत्पादनों के साथ ही चंदन की खेती, बाँस उत्पादन, औषधियों के निर्माण में उपयोगी वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए वनों को बचाना भी आवश्यक है और वनों से वनवासियों को आय भी हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। मेले में बायर-सेलर मीट के आयोजन प्रशंसनीय हैं। इसके अधिकाधिक आयोजन हों ताकि वनवासियों को वनोपज का दाम मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान लाल परेड ग्राउंड में वन विभाग द्वारा आयोजित अतंर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। वन मंत्री कुवंर विजय शाह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, आयुष राज्य मंत्री श्री राम किशोर कावरे, प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, जन-प्रतिनिधि और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए वन समितियों के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंटरनेशनल हर्बल मेले में विभिन्न स्टाल देखे और उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

विंध्या उत्पाद खरीदें, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ब्रांडिंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विंध्या हर्बल के उत्पाद उपयोग में लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा हर्बल चाय, शहद, चिरौंजी हमारे ब्रांड हैं। इन्हें खरीदें और प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा ये शुद्धता से भरपूर उत्पाद हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन समितियों के सदस्यों ने विभिन्न वन उत्पाद, वन मेले में प्रदर्शित किए हैं।

आयुर्वेद प्राचीन विद्या, इसका भी उपयोग करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्राचीन विधा है। हर ग्राम में इसके जानकार होते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के वैद्य पं. रामायण शास्त्री का उल्लेख किया जो खाने-पीने की चीजों में औषधि देते थे, हजारों रोगियों को इसका लाभ मिलता था। ऐलोपेथी के साथ आयुर्वेद का उपयोग भी करना उपयोगी है।

वन समितियाँ बाँस उत्पाद को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विश्व को बेहतर औषधियाँ चाहिए, जो हमें वनों से प्राप्त हो सकती हैं। हम दुनिया को औषधियाँ देकर मदद कर सकते हैं और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वनोपज से जुड़े भाई-बहनों को आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाँस की मांग बढ़ती जा रही है। इसका क्षेत्र बढ़ रहा है। बाँस से फर्नीचर बनाने और सजावटी सामान के साथ इसके उपयोग का दायरा बढ़ रहा है। वन समितियाँ बाँस के उत्पाद को बढ़ावा दें और बेहतर मुनाफा कमाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने तेंदूपत्ते के अलावा अन्य वनोपज को खरीदने की भी व्यवस्था की है। हमारे वनों में अनेक औषधीय पेड़-पौधे हैं। इनसे दवाएँ बन रही हैं। वन मेला अब भव्य स्वरूप में है। यह हमें औषधियों से इलाज देता है, तो रोजगार के अच्छे अवसर भी देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के समय, हमारी औषधियों ने बहुत बड़ा सहारा दिया।

वन ऑक्सीजन प्लांट हैं, औषधियों के मामले में भी धनी हैं वन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे मध्यप्रदेश के वन देश का ऑक्सीजन प्लांट हैं। साथ ही हमारे वन हमेशा से औषधियों के मामले में धनी हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों से बोले गडकरी : ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू करें, 'अन्नदाता' ही नहीं 'ऊर्जादाता' भी बनेंगे

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताया और किसानों से कहा कि उन्हें इसका उत्पादन शुरू करना चाहिए और एक बड़े अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन वैकल्पिक ईंधनों का भविष्य है और बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए देश के किसानों को इसके उत्पादन की ओर अब ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

गडकरी ने यह बात 'एग्रोविजन' की ओर से आयोजित एक प्रदर्शनी के

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कही। गडकरी इस संगठन के मुख्य संरक्षक भी हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

कोयले का विकल्प साबित हो सकती है ग्रीन हाइड्रोजन

यहां नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण बायो-मास, बायो-ऑर्गेनिक वेस्ट और गंदे पानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश में कोयले के आयात का विकल्प साबित हो सकता है।

देश के किसान 'अन्नदाता' के साथ 'ऊर्जादाता' भी बनेंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि एग्रोविजन की शुरुआत किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए की गई थी। देश के किसान अब केवल 'अन्नदाता' के साथ-साथ 'ऊर्जादाता' भी बनेंगे।

भविष्य का ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन, शुरू करें उत्पादन

उन्होंने कहा, 'स्टील प्लांट, ट्रैक्टर, बस, रेलवे और अन्य उद्योग केवल ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगे। यही भविष्य है और अब किसानों को एथेनॉल, बायो-एलएनजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी शुरू करना चाहिए।'

अब आजीविका मिशन से जुड़कर गतिविधियों को बढ़ाएंगे तेजस्विनी समूह : मुख्यमंत्री श्री चौहान

महिला सशक्तिकरण कार्यों को मिलेगी नई गति ● तेजस्विनी समूहों की पारंपरिक पहचान को रखा जाएगा कायम

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम में कार्यरत समूह अब आजीविका मिशन में कार्य करेंगे। महिला सशक्तिकरण कार्यों को नई गति प्रदान की जाएगी। तेजस्विनी समूह की गतिविधियों को तेज करने में आजीविका मिशन पूरा सहयोग करेगा। इन समूहों को अधिक सशक्त बनाकर सदस्य बहनों की आय वृद्धि, आत्म-निर्भरता और आर्थिक संबल के लाभ भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेजस्विनी के समूहों की पारंपरिक पहचान को कायम रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी के क्रियान्वयन की गतिविधियों के संबंध में बैठक संपन्न हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल भी उपस्थित थे।

स्व-सहायता समूहों का होगा मिशन में विलय

उल्लेखनीय है कि गत 16 दिसंबर को मंत्रि-परिषद् ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्व-सहायता समूहों के कार्य-क्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए उनका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इस समय ग्राम स्तर के 16 हजार 749 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं। ग्राम स्तर पर 2 हजार 624 समितियाँ और विकास खण्ड स्तर पर 60 महिला महासंघ कार्य कर रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ

देश में करीब 80 लाख महिला सदस्यों में से सवा दो लाख सदस्य मध्यप्रदेश की हैं। यह प्रतिशत राष्ट्रीय भागीदारी में 2.7 है। प्रदेश के 6 जिलों में क्रियान्वित तेजस्विनी कार्यक्रम में तीन जिले सागर संभाग और तीन जिले जबलपुर संभाग के शामिल हैं। वर्तमान में तेजस्विनी समूह 51 करोड़ 24 लाख रूपये की बचत कर चुके हैं। छह जिलों मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर में कृषि कार्य के अलावा डेयरी, सब्जी उत्पादन, बकरी पालन, किचन गार्डन, उद्यानिकी, पोल्ट्री, टेलरिंग जैसी गतिविधियों से 2 लाख 15 हजार महिलाएँ संलग्न हैं। महिला महासंघ कोदो प्र-संस्करण, टमाटर केचअप, गुड़ चिक्की, मिल्क चिलिंग सेंटर, पशु संवर्धन केंद्र, पावरलूम इकाई, पैकेजिंग इकाई और वर्मी कम्पोस्ट की गतिविधियों में संलग्न हैं। विपणन गतिविधियों में अन्दाई और भारती ब्रांड का पंजीयन कराया गया है। इसके लिए पोर्टल भी विकसित किया गया है। तेजस्विनी कार्यक्रम में सदस्यों की आय में काफी वृद्धि हुई है। एक सदस्य की औसत मासिक आय 2,176 रूपये से बढ़कर 6,190 रूपये हो गई है। योजना आयोग द्वारा भी इसका अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में ग्राम सभा में भी महिलाओं की भागीदारी 62 प्रतिशत है। डिंडोरी की कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी इकाई, गोंडी फेब्रिक और हैंडलूम इकाई, मंडला में ऑर्गेनिक मसाला इकाई ने विशेष पहचान बनाई है। इसी तरह गणवेश सिलाई और आपूर्ति, जनता बीड़ी उत्पादन, गुड़ पट्टी और अलसी प्रोसेसिंग एवं उत्पादन इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं। सागर संभाग के तीन जिलों छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में मिल्क कलेक्शन सेंटर कार्य कर रहे हैं।

नेतृत्व के लिए भी समर्थ बनी हैं समूह की महिलाएँ

प्रदेश में तेजस्विनी महिला स्व-सहायता समूहों की 4 हजार 321 सदस्य पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनीं थीं। इनमें से 1929 सदस्य सफलतापूर्वक पंचायत राज संस्थान में सदस्य बन चुकी हैं। प्रदेश में तेजस्विनी कार्यक्रम से जुड़ी 194 महिलाएँ पंचायतों का नेतृत्व भी कर रही हैं। जनजातीय समुदाय से महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी पंचायत पदाधिकारी महिलाएँ परिसंघों की आजीविका और आय के स्रोत विकसित करने की उपलब्धि भी हासिल कर चुकी हैं।

उत्पादकता संवर्धन के लिये प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में कर रही है मदद - मुख्य सचिव श्री बैंस

मुख्यमंत्री की मंशानुसार आगामी 3 वर्षों का एक्शन प्लॉन तैयार करेंगे - एपीसी श्री सिंह

कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग के साथ एक्सटेंशन पर भी है जोर - एसीएस श्री केसरी

दलहन उत्पादन में आत्म-निर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

भोपाल :कृषि क्षेत्र में उत्पादन संवर्धन संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिये सरकार सतत मदद कर रही है। इसके लिये आवश्यक प्रावधान भी किये जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने भोपाल में "दलहन उत्पादन में आत्म-निर्भरता" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उक्त विचार व्यक्त किये।

मुख्य सचिव श्री बैंस ने कहा कि दलहन क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लिये नवाचारों के साथ ही पूर्व संचालित व्यवस्थाओं और प्रबंधों को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके लिये हमें क्रॉप, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्लस्टर इत्यादि को भी आइडेंटिफाई करके प्रोत्साहित करना होगा। आत्म-निर्भरता के लिये हम मात्र कृषि विश्वविद्यालयों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हम सभी को मिलकर इसके लिये प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषिगत उद्योगों के सेटअप और उत्पादन सुविधाओं के संवर्धन के लिये व्यापक स्तर पर सुविधाएँ देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने दीर्घकालीन योजनाओं पर भी कार्य करने पर जोर दिया।

संगोष्ठी के विशेष अतिथि भारत सरकार के संयुक्त सचिव कृषि (बीज) श्री अश्विनी कुमार ने देश में दलहन की वर्तमान स्थिति, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में दलहन के उत्पादन की संभावनाएँ एवं दालों के विपणन, मूल्य एवं मूल्य संवर्धन पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आगामी 3 वर्षों के लिये एक्शन प्लॉन तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिये हैं।

शुभारंभ-सत्र में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग के साथ ही किसानों को कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री केसरी ने कहा कि दलहन में आत्म-निर्भरता के लिये हम कृषि सिनेरियो की उत्कृष्टता के हर बिन्दु पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिये मार्केटिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, उत्पादकता में वृद्धि, पैकेजिंग इत्यादि पर भी कार्य किया जा रहा है। न्यू थाट प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत सरकार के एडीजी आइल सीड एण्ड पल्सेस श्री संजीव गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश दलहन और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिये सबसे बेहतर मेकेनिज्म मध्यप्रदेश में विकसित किया गया है। मध्यप्रदेश की खासियत है कि यहाँ की किसी भी क्रॉप पर महामारी नहीं आई है।

एक दिवसीय यह संगोष्ठी पाँच सत्र में हुई। इसमें दालों के उत्पादन, विपणन, बीमा, बीज उत्पादन, पैकेजिंग, निजी संस्थाओं के माध्यम से पीपीपी मॉडल, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), कृषि उत्पादक संस्थाओं (एफपीओ) और कृषि यंत्रीकरण की दाल उत्पादन में भूमिका, व्यापार एवं मूल्य संवर्धन इत्यादि विषयों पर विषय-विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। सभी सत्र में विभिन्न विषय-विशेषज्ञों और वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किये गये।

संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने संगोष्ठी के उद्देश्यों से अवगत कराया।

कार्यक्रम में श्री विकास नरवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, संचालक, श्री राजीव चौधरी, संचालक, कृषि अभियांत्रिकी सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैंकर्स स्व-रोजगर योजनाओं का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें : मुख्यमंत्री

निजी बैंक सामाजिक दायित्व भी निभाएँ

12 जनवरी को आयोजित स्व-रोजगार मेले में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभायें

हर माह लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करें

सीएम हेल्प लाइन में शिकायतें आना बैंकों की प्रतिष्ठा के अनुरुप नहीं

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंकर्स स्व-रोजगार योजनाओं का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें। भारत सरकार की स्व-रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।

रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन एवं बेहतर परिणाम लाने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विशेष रूप से स्व-रोजगार योजनाओं का प्रथमिकता से क्रियान्वयन करें। आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से चलें। स्व-रोजगार के लिए व्यवस्थित ढंग से जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऋण शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय स्व-रोजगार मेला

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राज्य स्तरीय स्व-रोजगार मेले का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि मेले में अधिकाधिक प्रकरणों में ऋण स्वीकृत करें। जिला स्तर पर भी शिविर आयोजित किए जाएँ। उन्होंने कहा कि विगत 9 नवम्बर से 26 नवम्बर तक 117 क्रेडिट कैंप आयोजित कर 51 करोड़ रूपये के मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए। इसी तरह प्रगति बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में लक्ष्य के मुताबिक प्रगति बढ़ायें। योजना में 5 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है। इसके लिए बैंक गंभीरता से कार्य करें। निजी बैंक ठीक से क्रियान्वयन करें। अभी तक लगभग 2 लाख 82 हजार प्रकरणों में ऋण स्वीकृति जारी की गई है।

हर माह होगी स्व-रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक माह स्व-रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करुंगा। सभी बैंकर्स गंभीरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निजी बैंकों का परफार्मेंस ठीक नहीं है। भारत सरकार की योजनाओं में लापरवाही न बरतें।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में म.प्र. देश में अव्वल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रगति अच्छी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अच्छा कार्य किया है। इस योजना में हम देश में अव्वल हैं। योजनांतर्गत लक्ष्य की 115 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। भारत सरकार द्वारा 4.05 लाख का लक्ष्य दिया गया था।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7022 परियोजनाओं एवं 211 करोड़ मार्जिन मनी स्वीकृति का लक्ष्य है, जिसे समय पर पूरा करें। प्राइवेट बैंक हर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे हैं। वे अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें। हर हालत में लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करें।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की इस माह प्रगति अच्छी है। निजी बैंक बेहतर ढंग से कार्य कर लक्ष्य पूरा करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में तेजी से प्रगति बढ़ाई जाये। राष्ट्रीय निजी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्य समय पर पूरा करें। लक्ष्य हर माह के लिए तय किये जाएँ और उसे उसी माह में पूरा करें। वार्षिक या त्रैमासिक लक्ष्य होने से समय पर पूरा करने में कठिनाई होती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक महीने में अच्छी प्रगति हुई है। योजना का लक्ष्य समय-सीमा में पूरा करें।

सीएम हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में तीन सौ दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों का तेजी से निराकरण करें। शिकायतें आना बैंकों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति बनायें कि सबको आनंद और प्रसन्नता हो। संतुष्टि के साथ निराकरण करें। पात्र नहीं होने पर ही फोर्स क्लोज करें।

डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बैठकें हर माह हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें हर महीने हों। स्व-सहायता समूह की महिलाएँ अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्हें हर तरह की मदद पहुँचाएँ।

ड्रोन सिंचाई तकनीक कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उन्नति लायेगी - पर्यावरण मंत्री श्री डंग

भोपाल : पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि ड्रोन सिंचाई तकनीक कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उन्नति लायेगी। परम्परागत सिंचाई में जहाँ एक हेक्टेयर क्षेत्र में 300 से 500 लीटर जल से 7 घंटे में, ट्रेक्टर स्प्रेयर से 2 घंटे में सिंचाई होती है, वहीं ड्रोन मात्र 20 मिनिट में 90 प्रतिशत कम जल (25 लीटर) से सिंचाई करता है।

श्री डंग ने यह बात आज होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में "डेयरी एवं गौ-शालाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट गोबर, गौ-मूत्र एवं गंदे पानी के वैज्ञानिक पद्धति से पुन: उपयोग" पर केन्द्रित एक-दिवसीय विचार गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कही। श्री डंग ने केन्द्र में ड्रोन सिंचाई का अवलोकन भी किया। संगोष्ठी में विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा और श्री ठाकुरदास नागवंशी भी मौजूद थे। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल और भाऊ साहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई।

श्री डंग ने कहा कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे नालियों और हेण्ड-पम्प के पास पानी जमा न होने दें। गौ-शालाओं के सुचारु संचालन के लिये जन-साधारण को भी योगदान के लिये प्रेरित करें। गायों से उत्पन्न गौ-मूत्र, गोबर से निर्मित खाद, दवाइयाँ, पेस्टीसाइड, फिनाइल आदि लोकप्रिय हो रहे हैं। इनकी अच्छी मार्केटिंग कर गौ-शालाओं को मजबूत बनायें। मुख्य वक्ता श्री सुरेश सोनी ने कहा कि पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर के स्थान पर बॉयो पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें।

सदस्य सचिव श्री ए.एन. मिश्रा ने पराली से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये विशेष कार्य करने और इसका औद्योगिक उपयोग करने के बारे में सुझाव दिया। वैज्ञानिक डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना, डॉ. प्रवीण सोलंकी, श्री मोहन नागर और श्री अनिल अग्रवाल ने भी गौकाष्ठ, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले विभिन्न उत्पादों आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया।

जमीन और हमारी सेहत के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाना जरूरी - कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की खेती की उर्वरता को बचाने और किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है तथा उसे पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने प्राकृतिक खेती के इस सेमीनार के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करने का काम किया है।

मंत्री श्री पटेल ने कृषि उपज मंडी सीहोर में यह बात कही। वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधन वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ सीहोर विधायक श्री सुदेश राय, वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि श्री दर्शन सिंह चौधरी सहित अनेक जन-प्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, यह चिन्ताजनक है। रासायानिक खादों के उपयोग से एक और जहाँ भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, वहीं इसके उपयोग से आने वाली फसल भी मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, भूमि की उर्वरता बनाए रखने और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के अनेक किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है।

श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है तथा कृषि नीतियों में संशोधन कर किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। श्री पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश दुनिया में एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को दस हजार रूपए दिए जा रहे हैं। यह राशि छोटे किसानों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि चने की खरीदी गेहूँ से पहले की, इसका लाभ किसानों को मिला और चना मूंग खरीदी की सीमा समाप्त की, जिससे किसान का जितना पंजीयन है उतनी फसल एक बार में ही ली जा सके।

श्री पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रारंभ में उनके पास जितनी खेती है, उसके एक चौथाई या उनकी सुविधानुसार जमीन पर प्राकृतिक खेती के द्वारा फसल ले सकते हैं।

उन्होंने उपस्थित सभी किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने का संकल्प भी दिलाया। श्री पटेल ने जैविक पद्धति से खेती करने वाले कोलासकलां के किसान श्री गजराज सिंह वर्मा को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देखा।

जैविक खेती को अपनाने उद्यानिकी विभाग की नई पहल

जैविक खेती से अवगत कराने किसानों को जैविक कृषि फार्मों का भ्रमण कराया जायेगा उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि जैविक खेती से अवगत कराने के लिये प्रदेश के किसानों को सफलतम जैविक कृषि फार्मों पर भेजा जायेगा। उद्यानिकी विभाग ने चयनित 20 मॉडल विकासखण्ड में से जैविक खेती के लिये 6 विकासखण्ड का चयन किया है। उद्यानिकी विभाग जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये नई पहल करने जा रहा है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह मंत्रालय में जैविक खेती कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि जैविक खेती के लिये चयनित सभी मॉडल विकासखण्डों में 50-50 हेक्टेयर के जैविक खेती करने वाले किसानों के क्लस्टर बनाये गये हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 50 और 50 से अधिक किसान हैं। इन किसानों के

समूह को सफलतम जैविक कृषि करने वाले कृषि फार्मों में भेजा जायेगा। मॉडल विकासखण्डों में जैविक खेती कर रहे किसानों और जैविक खेती के रकबे को भी चिन्हित किया गया है। यह किसान प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले प्रेरक बनेंगे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता देने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा जैविक खेती के लिये चिन्हांकित 6 मॉडल विकासखण्ड में बड़वानी जिले का पाटी विकासखण्ड, श्योपुर जिले का कराहल, झाबुआ जिले का झाबुआ, बालाघाट जिले का परसवाड़ा, मण्डला जिले का नारायणगंज और शहडोल जिले का गोहपारु विकासखण्ड शामिल है।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने चालू वित्तीय सत्र में योजनावार लक्ष्य और अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिये हर संभव प्रयास करें। प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त उद्यानिकी श्री एम.के. अग्रवाल, एम.डी. एम.पी. एग्रो श्री राजीव जैन बैठक में उपस्थित थे।

ड्रोन से किसानों को होगा फायदा, रोजगार भी बढ़ेंगे – श्री तोमर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को अधिसूचित करने के साथ ही ड्रोन नियम-2021 को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही, कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के अनुप्रयोग के लिए "मानक संचालन प्रक्रिया" (एसओपी) बनाई गई है, जिसे कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफी फायदा होगा, वहीं रोजगार भी बढेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडा में से एक है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के साथ-साथ दक्षता बढ़ाई जा सकें। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सभी नियम व सावधानियों के साथ ड्रोन पालिसी का आज एक नया आयाम जुड़ा है। श्री तोमर ने जिक्र किया कि पिछले साल देश में टिड्डियों के प्रकोप को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय व राज्य सरकारों की मदद से ड्रोन सहित नई टेक्नालाजी के माध्यम से नियंत्रण किया गया था।

श्री तोमर ने कहा कि कृषि प्रधान हमारे देश में केंद्र व राज्यों की नीतियां हमेशा कृषि व कृषक को प्राथमिकता में रखकर तैयार की जाती है। कृषि क्षेत्र की प्रगति में किसानों व वैज्ञानिकों का योगदान बढ़-चढ़कर रहता है, वहीं सरकार की जिम्मेदारियों व किसान हितैषी नीतियों से अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक या दो पर है। श्री तोमर ने कहा कि आज उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही बेहतर गुणवत्ता व वैश्विक मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पादों की आवश्यकता है। वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री जी का जोर रहा है कि किसानों की आय दोगुनी होना चाहिए, इस दृष्टि से योजनाओं का सृजन किया गया है तथा किसानों के खातों में नकदी भी पहुंचाने का अभूतपूर्व काम हुआ है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि साहूकारों पर किसानों की निर्भरता कम करने व उन्हें खेती के लिए आसान ऋण दिलाने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चलाया है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा निजी निवेश के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन द्वारा किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने, उन्हें टेक्नालाजी का लाभ पहुंचाने, प्रोसेसिंग व मोल-भाव करने की सुविधा देने आदि की शुरूआत भी हो चुकी है। ये योजनाएं किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे। कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने भी संबोधित किया। संयुक्त सचिव श्रीमती शोमिता बिस्वास ने संचालन किया और ड्रोन एसओपी के संबंध में प्रेजेन्टेशन दिया। संयुक्त सचिव श्री प्रमोद मेहरदा ने आभार माना। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, राज्यों के अधिकारी, कस्टम हायरिंग केंद्रों के संचालक भी कार्यक्रम से जुड़े थे।

राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार कर रहा मंत्रालय

इसमें सहकारी यूनियनों फेडरेशन राज्य सरकार समेत इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से चर्चा के बाद इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए सहकारी आंकड़ों का वैज्ञानिक व तथ्यपूर्ण होना बहुत जरूरी होता है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श शुरु कर दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र का डाटाबेस तैयार करने में भी जुट गई है ताकि प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारिता नीति की जल्दी घोषणा की जा सके। केंद्रीय सहकारिता सचिव डी.के. सिंह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के आंकड़े तो हैं लेकिन उसे बहुत वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उसका आधिकारिक रुप से तैयार किया जा रहा है। सिंह रुरल वायस के आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोग सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बारे में क्षेत्रवार जानकारी चाहते हैं। किस सेक्टर में कितनी सहकारी संस्थाएं सक्रिय हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन वे वैज्ञानिक नहीं कहे जा सकते हैं।

सहकारी संस्थाओं के मौजूदा आंकड़े नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एसीयूआई) ने तैयार किये हैं। लेकिन मंत्रालय के पास अपने कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं हैं। सरकार अपने स्तर पर वैज्ञानिक तरीके डाटाबेस तैयार करे, जिससे प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी नीतियों के अमल में सहूलियत हो सके। इसके लिए कंसलटेशन प्रोसेस चालू है। एनसीयूआई के आंकड़े के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 8.6 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इनमे सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं की संख्या कुल 63 हजार ही है। जबकि आंकड़ों में इसकी संख्या 90 हजार से भी अधिक है। आंकड़ों के सही होने के बाद स्थितियों में सुधार आएगा। सहकारिता सचिव सिंह ने कहा 'राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा में थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसके लिए कई स्तरों पर विचार-विमर्श शुरु कर दिया गया है। इसमें सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकारों से गहन विचार किया जाएगा।

इसमें सहकारी यूनियनों, फेडरेशन, राज्य सरकार समेत इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से चर्चा के बाद इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए सहकारी आंकड़ों का वैज्ञानिक व तथ्यपूर्ण होना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि इस पूरी कवायद में सालभर का समय लग सकता है। सिंह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पहले चरण में तीन प्रमुख क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्युटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालय को कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने सभी का सहयोग मांगा है। मंत्रालय ने आईआईएम, आईआईटी और आईआईआईटी को पत्र लिखकर उनका सुझाव मांगा है ताकि सहकारी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है।

कुछ संस्थानों से सुझाव मिलने भी लगे हैं, बाकी के सुझावों का इंतजार है।इसके पूर्व रुरल वायस के कार्यक्रम में नेशनल कोआपरेटिव डवलपमेंट कारपोरेशन (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि उनका पूरा जोर ग्रामीण ऋण वितरण पर रहता है। पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एनसीडीसी ने जहां 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया वह चालू वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने सहकारिता क्षेत्र की हालत पर चिंता जताने के अंदाज में कहा कि अमूल और ईफको को छोड़ दिया जाए तो बाकी के हालत ऐसी ही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल किसान सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। सहकारिता क्षेत्र को कर्ज बांटने वाली संस्था से अलग हटकर उसका कार्य का दायरा बढाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। ईफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा कि लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं की सूची में पहला नंबर ईफको और दूसरे नंबर पर अमूल बना हुआ है।

देश में सहकारिता प्रशिक्षण के लिए बनेंगे विश्वविद्यालय

पुणे। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा शिवाजी महाराज ने न्याय, समाज कल्याण और आत्मरक्षा के लिये व्यूह रचना, सैन्य निर्माण, सैन्य का आधुनिकीकरण और 18वीं शताब्दी में सबसे पहली नौसेना बनाने का काम किया। सहकारिता विभाग के काम करने में आत्म संतोष है और सामर्थ भी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द सहकारिता प्रशिक्षण के लिए पाठयक्रमों के साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके कॉलेज होंगे, जिसमें सहकारिता की ट्रेनिंग दी जायेगी। शाह ने कहा कि यदि हम सहकारी व्यवसाय का विस्तार करना चाहते है, तो हमें अगले 25 वर्षों के लिये सहकारिता को अमली-

जामा पहनाने वाली योजना लागू करनी होगी। इसके लिये सहकारिता मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य में सहकारिता विभाग और सहकारिता आंदोलन का बड़ा हाथ होगा।

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं सहकारी निरीक्षकों हेतु गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारी संस्थाओं में गबन, धोखाधड़ी एवं अंकेक्षण तथा विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर दिनांक 13 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021 व 20 दिसम्बर 2021 से 22 दिसम्बर 2021 एव 27 दिसम्बर 2021 से 29 दिसम्बर 2021 तक कुल 46 प्रतिभागियों ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान विषय पर श्री डी.के. सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा/अधिवक्ता, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, विषय पर श्री अविनाश सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज पर श्री के के सक्सेना, से.नि. डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन, गबन, धोखाधडी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान विषय पर श्री जे एम चतुर्वेदी, से.नि. जिला न्यायाधीश, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों का परीक्षण, तकनीकी पैरामीटर के आधार पर– सी.आर., ए.आर., एन.पी.ए. एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना विषय पर श्री पी.के.एस. परिहार, वरिष्ठ प्रबंधक अपेक्स बैंक, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधडी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण, कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन, कर्तव्य, उत्तरदायित्व व द्वारा प्रशासक निर्वाचन अधिकारी, परिसमापन, अंकेक्षण विषय पर श्री जे.पी.गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, सहकारिता, संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउंट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की जानकारी प्राप्त करना विषय पर श्री आर.के. गंगेले, ओ.एस.डी., अपेक्स बैंक, संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी(जी.एस.टी., आयकर आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना विषय पर श्री अंशुल अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सहकारी संस्था को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं पृथक वैधानिक प्रतिवेदन की जानकारी श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम विषय पर श्री संजीव गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, व्यक्तित्व विकास, संवैगात्मक बुद्धि, समय एवं तनाव प्रबंधन विषय पर श्रीमति सृष्टि उमेकर एवं श्रीमति रश्मि गोलिया, कारपोरेट मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, राज्य संघ एवं श्री संजय सिंह, राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गये। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमति रेखा पिप्पल, व्याख्याता एवं श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य के द्वारा किया गया। श्री विनोद कुशवाहा, श्री लोकेश श्रीवास्तव, श्री विक्रम मजूमदार, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री धनराज सैंदाणे, श्री ज्ञानू सिंह एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।

(पृष्ठ 1 का शेष)

वनोपज विक्रय कार्य का होगा विकेन्द्रीकरण....

वनोपज हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन वनों से हमें स्वस्थ रहने की अमृत समान औषधियाँ मिलती हैं। वनोपज से तैयार की गई दवाएँ शुद्ध होती हैं। वनों के संरक्षण के साथ औषधियों के उत्पाद पर भी हम काम कर रहे हैं। यह औषधियाँ हमें उत्तम स्वास्थ्य के साथ बेहतर आमदनी भी देती हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने तेंदूपत्ते के अलावा अन्य वनोपज को खरीदने की भी व्यवस्था की है। हमारे वनों में अनेक औषधीय पेड़-पौधे हैं। इनसे दवाएँ बन रही हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और हमारे वनवासी भाई-बहनों की आमदनी भी बढ़ रही है। यह वन मेला सिर्फ वन मेला न होकर अद्भुत आयोजन बन गया है।

कोरोना से बचाव के लिए सावधानियाँ बरतने का आव्हान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है। हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क का उपयोग आवश्यक है। हम आवश्यक सावधानियों से ही कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन का रिकार्ड बना है। प्रत्येक व्यक्ति को दो डोज लगवाना है।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक काढ़े ने लाखों लोगों को महामारी से बचाया। मध्यप्रदेश ने आयुर्वेद के इस उत्पाद का प्रयोग कर दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत किया। वन मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसके आयोजन का उद्देश्य वनोपज उत्पाद करने वाले वनवासियों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके तथा बिचोलियों से उन्हें बचाया जा सके। दो दिन तक वनवासियों को यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वन मंत्री श्री शाह ने कहा कि मेले में पहली बार 6-7 विदेशों के आयुर्वेद डॉक्टर भाग ले रहे हैं। इसके माध्यम से छोटे और गरीब लोग आकर उनसे इलाज भी करा सकते हैं। आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी डॉक्टरों से इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनेक वन समितियों के सदस्यों से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रतीक स्वरूप विंध्या हर्बल के उत्पाद भेंट किए गए।

मेले के मुख्य आकर्षण

अंतराष्ट्रीय वन मेले में लगभग 300 स्टॉल स्थापित की गई है, जिसमें मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि के हर्बल उत्पादक शामिल हुए है। हर्बल उत्पादों विशेषकर कच्चे माल से लेकर प्र-संस्कृत उत्पादों एवं इससे संबंधित तकनीक का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं को भी मेले में प्रदर्शित किया गया। मेले में चिकित्सा परामर्श के लिये ओपीडी स्टॉल सहित आयुर्वेद चिकित्सक/वैद्यों द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था भी रखी गई है। वन मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सूफी गायन, आदिवासी लोकनृत्य एवं मालवी लोकगीत भी होंगे।

लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा थीम पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी होगा इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के विषय-विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। मेले में इस वर्ष भी लघु वनोपज के क्रय-विक्रय के लिये क्रेता-विक्रेता संवाद सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

सहकारिता विभाग के सहायक ग्रेड- 1,2 एवं 3 कर्मचारियों हेतु कार्यालयीन कार्य निष्पाादन विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा सहकारिता विभाग के कर्मचारियों हेतु दो दिवसीय "कार्यालीयन कार्य निष्पाएदन प्रशिक्षण कार्यक्रम" दिनांक 29.09.2021 से 24.12.2021 तक कुल 10 कार्यक्रम श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक के मार्गदर्शन आयोजित किये गये। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के 191 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुये श्री संजय कुमार सिंह राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण सहकारिता विभाग के सहायक ग्रेड- 1,2,3 कर्मचारियों हेतु दो दिवसीय कार्यालयीन कार्य निष्पादन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें विषय-विशेषज्ञों द्वारा मध्यप्रदेश मूलभूत नियम (अवकाश नियम, यात्रा भत्ता नियम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भण्डार क्रय नियम आदि), मध्यप्रदेश मूलभूत नियम (सर्विस बुक निर्धारण वेतन वृद्धि एवं भत्ते आदि) श्री यू.एस. ठाकुर, से.नि. उपसचिव (लेखा) के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पत्राचार (डाक प्राप्ति एवं वितरण, नोटशीट लेखन, नस्तीकरण एवं प्रस्तुतीकरण) पत्र लेखन, पत्रों के प्रकार (परिपत्र , अर्द्वशासकीय पत्र, अधिसूचना, आदेश आदि पत्रलेखन) श्री देवीसिंह नेवारे, से.नि. संयुक्त संचालक (वित्त) के द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य व कार्य का निष्पादन, सीटीजन चार्टर व सूचना का अधिकार अधिनियम, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1956 श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। विधि कक्ष / रीडर / विधान-सभा की जानकारी संकलन, नोटशीट लेखन, सूचना-पत्र जारी करना तथा नस्तियों का संधारण श्री अविनाश सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। कर्मचारियों से खुली चर्चा श्री जी.डी. नथानी, अधीक्षक कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. के द्वारा की गई।

कार्यक्रम से समापन अवसर पर सभी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक एवं श्री संजय कुमार सिंह राज्य सहकारी अधिकारी द्वारा वितरित किये गये। इन कार्यक्रमों का समन्वय श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य द्वारा किया गया। श्री विनोद कुशवाहा, श्री विक्रम मजूमदार, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री लोकेश श्रीवास्तव एवं राज्य सहकारी संघ भोपाल के समस्त स्टॉफ का विशेष सहयोग रहा।

कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां

कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी ही सुरक्षा – किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करता है एवं यह कीटनाशक जहरीले तथा मूल्यवान होते हैं, इन कीटनाशकों के प्रयोग की जानकारी के आभाव में कृषक एवं कृषक परिवार को जान जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसलिए कृषकों को इसके उपयोग की एवं उपयोग के बाद क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए इसकी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। कीटनाशकों के घातक प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक होता है की उन पर लिखे हुए निर्देशों का पालन सही तरीके से करें एवं किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

कीटनाशकों के प्रयोग से पहले सावधानियां

सर्वप्रथम किसानों को फसलों के शत्रु कीटों की पहचान कर लेना चाहिए, यदि पहचान संभव नहीं है तो स्थानीय स्तर पर उपस्थित कृषि विशेषज्ञ से कीट की पहचान करवा कर कीट के अनुरूप कीटनाशी का क्रय करना चाहिए।

- कीटनाशक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कीट द्वारा आर्थिक नुकसान की क्षति निम्न स्तर की सीमा से अधिक हो गयी हो।
- कीट को मारने का सही तरीका एवं समय का ध्यान रखना चाहिए।
- कीटनाशकों के विषाक्ता को प्रदर्शित करने के लिए कीटनाशक के डिब्बे पर तिकोने आकार का हरा, नीला, पीला एवं लाल रंग का निशान बना होता है। सबसे पहले लाल निशान वाले कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योकि लाल निशान के कीटनाशी समस्त स्तनधारियों पर सबसे अधिक नुकसान करते है। लाल निशान वाले कीटनाशी की अपेक्षा पीले रंग के निशान वाले कीटनाशी कम तथा पीले रंग के कीटनाशी की अपेक्षा नीले रंग के निशान वाले कम नुकसान पहुंचाते है। सबसे कम नुकसान हरे रंग के निशान वाले कीटनाशी से होता है।
- कीटनाशक खरीदते समय हमेशा उसके उत्पादन की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि को अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि पुरानी दवाई को खरीदने से बचा जा सके क्योंकि पुरानी दवा कम अथवा नहीं के बराबर असरदार हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।
- कीटनाशक के पैकिंग के साथ एक उपयोग करने के लिए निर्देशिका पुस्तिका अथवा लीफलेट को ध्यानपूर्वक पडना आवश्यक है, जिससे उपयोग का तरीका तथा मात्रा प्रयोग की जा सकती है।
- कीटनाशकों का भण्डारण हमेशा साफ सुथरी, हवादार एवं सूखे स्थान पर करें।
- यदि अलग – अलग समूहों के कीटनाशकों का प्रयोग करना हो तो एक के बाद दूसरे का प्रयोग करें।
- ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें जिसके प्रयोग से पत्तों में रासायनिक अम्ल बनता हो।

कीटनाशियों के प्रयोग के बाद सावधानियां

- बचे हुए घोल को कभी भी पम्प में नहीं छोड़ें।
- खली डिब्बे को किसी अन्य काम में नहीं लें बल्कि उसे नष्ट कर दें।
- कीटनाशी के छिडक़ाव के समय प्रयोग में लाये गए कपड़े, बर्तन को अच्छी तरह से धोकर रखें।
- जिस भी कीटनाशक का प्रयोग करें उसका सम्पूर्ण विवरण लिखकर रख लें।
- बचे हुए कीटनाशक की शेष मात्रा को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर दें।
- पम्प को अच्छी तरह से साफ करके सुरक्षित स्थान पर रखें।
- कीटनाशी के कागज या प्लास्टिक को यदि जलाना हो तो उसके धुंए के पास नहीं खड़ा हों।
- कीटनाशी के छिडक़ाव के बाद अच्छी तरह से स्नान करके दूसरे वस्त्र पहने।
- कीटनाशी छिडक़ाव के बाद छिडक़े गए खेत में किसी व्यक्ति एवं जानवर को नहीं जाने दें।
- कीटनाशी छिडक़ाव के बाद छ: घंटे तक वर्षा नहीं हो। यदि वर्षा हो जाये तो पुन: छिडक़ाव करें।
- अंतिम छिडक़ाव एवं फसल की कटाई ता तुड़ाई के समय दवा में बताये अंतराल का अवश्य ध्यान रखें।

विष का प्राथमिक उपचार

सभी प्रकार की सावधानी रखने के उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति इन कीटनाशकों का शिकार हो जाये तो निम्नलिखित सावधानियां अपनायें।

- रोगी के शरीर से विष को अति शीघ्र निकलने का प्रयास करें।
- विषमार दवा का तुरंत प्रयोग करें।
- रोगी को तुरंत पास के किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जायें।
- यदि जहर खा लिया हो तो एक ग्लास गुनगुने पानी में दो चम्मच नमक का घोल मिला कर उलटी करें।
- यदि व्यक्ति ने विष सूंघ लिया हो तो रोगी को शीघ्र खुले स्थान पर ले जायें, शरीर के कपड़े ढीले कर दें, यदि दौरे पड़ रहे हो तो अँधेरे स्थान पर के जायें।
- यदि साँस लेने परेशानी हो रही हो तो रोगी को पेट के सहारे लिटाकर उसकी बाँहों को सामने की और फैला लें एवं रोगी की पीठ को हल्के – हल्के सहलाते हुए दबाएं तथा कत्रिम श्वांस का प्रबंध करें।

इस प्रकार उपरोक्त सावधानियां को ध्यान में रखते हुए यदि कीटनाशियों का प्रयोग किया जाए तो इनसे होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है।

कीटनाशकों के प्रयोग करते समय सावधानियां

- शरीर को पूरी तरह से बचाने के लिये ऐसे कपड़े पहने जो पूरी तरह से शरीर को ढक सके जिससे यदि कीटनाशक रसायन कपड़ों पर लग जाये तो उसे बदला जा सकता है एवं हाथों में रबर के दस्ताने अवश्य पहनें तथा मुँह पर मास्क लगा लें एवं आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगा लें।
- बहुत जहरीले कीटनाशी को प्रयोग करते समय अकेले कार्य नहीं करें एक या दो व्यक्तियों को खेत के बाहर मौजूद रहें आपातकाल में जल्द मदद मिल सके।
- कीटनाशी को मिलाने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें तथा घोल को ढककर रखें ताकि उसे छोटे बच्चे एवं कोई पशु धोखे में पी न ले।
- कीटनाशी छिडक़ने वाले को छिडक़ाव की पूरी जानकारी हो तथा उसके शरीर पर कोई घाव नहीं हो तथा छिडक़ाव के समय चलने वाली हवा से बचें।
- कीटनाशी का घोल बनाते समय किसी बच्चे या अन्य आदमी या जानवर को पास में नहीं रहने दें।
- दवा के साथ मिली हुई प्रयोग पुस्तिका को अच्छे से पड़ कर उसके अनुसार कार्य करें।
- कीटनाशक का छिडक़ाव करने के पश्चात त्वचा को अच्छी तरह से साफ कर लें।
- छिडक़ाव के समय साफ पानी की पर्याप्त मात्रा पास में रखें।
- कीटनाशी मिलते समय जिस दिशा से हवा का बहाव हो रहा हे उसी दिशा में खड़े होकर कीटनाशी को मिलायें।
- कीटनाशी का धुंआ सांस के द्वारा शरीर के अंदर नहीं जाने दें।
- एक बार जितनी आवश्यकता हो उतना ही कीटनाशी ले जायें।
- कीटनाशक छिडक़ने वाले यंत्र की जाँच कर लें, यदि यंत्र सही काम नहीं कर रहा हो तो उसकी मरम्मत कर लें तथा नोजल को कभी भी मुँह से खोलने का प्रयास नहीं करें।
- तरल कीटनाशियों को सावधानीपूर्वक मशीन में डालें एवं यह ध्यान रखें की किसी भी प्रकार मुंह, कान, नाक, आँख आदि में रसायन न जाए। यदि गलती से ऐसा हो तो तुरंत साफ पानी से बार – बार प्रभावित अंग को धोयें।
- कीटनाशी का प्रयोग करते समय किसी प्रकार का धूम्रपान या कोई खान -पान नहीं करें।
- कीटनाशी का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित कर लें की कीटनाशी की मात्रा पूरी तरह से पानी में घुल गयी हो।
- हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर छिडक़ाव या भुरकाव करें
- छिडक़ाव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल का हो यथा यह ध्यान रखें की हवा की गति 7 किमी प्रति घंटा से कम ही हो तथा तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहना सर्वोत्तम होता है।
- फूल आने पर फसलों पर कम से कम छिडक़ाव करें और यदि छिडक़ाव करना हो तो हमेशा सायंकाल में ही छिडक़ाव करें, जिससे मधुमक्खियां रसायन से प्रभावित न हो।
- कीटनाशकों का व्यक्ति पर प्रभाव दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए साथ ही कीटनाशी का डिब्बा भी लेकर जायें।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जनवरी 2022

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

फरवरी 2022

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	
बुध	2	9	16*	23	
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

मार्च 2022

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

अप्रैल 2022

रवि		3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1†	8	15	22	29
शनि	2*	9	16	23	30

मई 2022

रवि	1	8	15	22	29
सोम	2	9	16	23	30
मंगल	3	10	17	24	31
बुध	4	11	18	25	
गुरु	5	12	19	26	
शुक्र	6	13	20	27	
शनि	7	14	21	28	

जून 2022

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9*	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	
शनि	4	11	18	25	

जुलाई 2022

रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

अगस्त 2022

रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	31
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

सितम्बर 2022

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	

अक्टूबर 2022

रवि	30	2	9	16	23
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

नवम्बर 2022

रवि		6	13	20	27
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15*	22	29
बुध	2	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26	

दिसम्बर 2022

रवि		4	11	18	25
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30
शनि	3	10	17	24	31

शासकीय अवकाश

26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 16* फरवरी संत रविदास जयन्ती, 1 मार्च महाशिवरात्रि, 18 मार्च होली, 1† अप्रैल बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी, 2* अप्रैल गुड़ी पड़वा/चैती चांद, 10 अप्रैल रामनवमी, 14 अप्रैल महावीर जयन्ती/ डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी, 15 अप्रैल पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), 3 मई परशुराम जयन्ती/ ईद-उल-फित्र, 16 मई बुद्ध पूर्णिमा, 9* जून बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस, 10जुलाई ईदुज्जुहा, 9 अगस्त मोहर्रम, 11 अगस्त रक्षाबंधन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त जन्माष्टमी, 2 अक्टूबर गाँधी जयन्ती, 5 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी), 8 अक्टूबर मिलाद-उन-नबी, 9 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकी जयन्ती, 24 अक्टूबर दीपावली, 8 नवम्बर गुरुनानक जयन्ती, 15* नवम्बर बिरसा मुंडा जयन्ती, 25 दिसम्बर ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)

* कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं. † केवल कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी है.

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।